जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 46 संख्याः 201 प्रभात बीकानेर, मंगलवार 11 फरवरी, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

अखिलेश, केजरीवाल व ममता, राहुल को अलग करके, अब एक नया राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की फिराक में

दिल्ली में केजरीवाल की हार से ज्यादा, कांग्रेस को तीसरी बार ''ज़ीरो'' सीट मिलने से इन पार्टियों के राजनीतिक सोच में परिवर्तन आया है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 फरवरी। दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी की सत्ता खोने से कहीं ज्यादा कांग्रेस की हार ने राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी एक नया राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी को बाहर रखा जाएगा।

अब जबकि भाजपा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चुनौती से निपट चुकी है, और अब यह पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी चुनावी मुहिम शुरू करने के लिए उत्साहित और आत्मविश्वास से भरी हुई है। आखिरकार, बंगाल में जीत पाना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ 42 लोकसभा सीटें है।

राहुल गांधी सभी तीनों दलों के लिए एक सिरदर्द रहे हैं और इन दलों को इस बात पर ऐतराज रहा है कि विपक्षी गठबंधन की कमान राहुल गांधी को मिल रही है। अब जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी तरह से नाकामयाब हो गई है, प्रमुख विपक्षी नेताओं को लगता है कि अब कमान उन्हें मिलनी चाहिए।

- ये तीनों पार्टियां, गांधी परिवार के उत्तराधिकारी को विपक्ष के गठबंधन का नेतृत्व मिलने से सदा से नाखुश थे और मानते थे, अब उनकी ''बारी'' आनी चाहिए।
- ममता बनर्जी की परन्तु दुविधा यह है कि वे विपक्ष के राष्ट्रीय गठबंधन के किसी घटक का बंगाल में कतई हस्तक्षेप बर्दास्त करने को तैयार नहीं हैं, पर, वे चाहती हैं, विपक्ष का गठबंधन उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व सौंपे।
- यह व्यवस्था विपक्ष के राष्ट्रीय गठबंधन को ग्राह्य नहीं है। ममता बनर्जी को दूसरी दिक्कत है, नये उत्साह से भरपूर भाजपा अब ममता बनर्जी के क्षत्रपों के भ्रष्टाचार के मामले पूरी ''गंभीरता'' से खोलने के लिये तैयार हो गई है।
- तथा, आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ ''रेप'' व हत्या का मामला भी पुनः जोर पकड़ रहा है और भाजपा उसको तन, मन, धन से चमोत्कर्ष पर ले जाना चाहती है।
- ममता बनर्जी के लिये पुलिस प्रशासन के पूर्ण ''सहयोग'' के बावजूत इस आंदोलन को दबा देना संभव नहीं लगता।

एक नया गठबंधन अलग नाम के साथ लॉन्च होने वाला है और इसका नेतृत्व अखिलेश यादव या ममता बनर्जी में से किसी एक के पास होगा। सूत्रों के अनुसार कुछ अन्य भी इस दौड़ में हैं।

बंगाल में, ममता बनर्जी अपने जनाधार पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। वह यह दावा कर रही हैं कि 2026 का अगला चुनाव भी उनका होगा। इसलिए वह प्रदेश में राष्ट्रीय विपक्षी पार्टियों के साथ किसी भी सहयोग को स्वीकार नहीं कर रही हैं, हालांकि बाकी जगहों पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति निलंबित

जोधपुर, 10 फरवरी (कास)। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने एक आदेश जारी कर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.के.एल श्रीवास्तव को कुलपति पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है। राज्यपाल ने संभागीय आयुक्त जोधपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें निलंबित किया है। जांच रिपोर्ट में प्रो. श्रीवास्तव के विरूद्ध पद का दुरूपयोग करने, राज कार्य में लापरवाही बरतने व विश्वविद्यालय को वित्तीय हानि पहुंचाने के गंभीर आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए।

- संभागीय आयुक्त की जाँच में दोषी पाये जाने पर राज्यपाल ने प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव को कुलपति पद से निलंबित किया।

प्रो. श्रीवास्तव के खिलाफ, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 (यथा संशोधित) की धारा 10(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन दिसंबर 2024 को संभागीय आयुक्त जोधपुर की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया था। इसमें वह दोषी पाए गए। राज्यपाल ने इस पर अधिनियम, 1962 (यथा संशोधित) की धारा 11क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'क्या ''सैक्युलरिज़्म'' का झण्डा फहराते रखना केवल हमारी जिम्मेवारी है?'

कांग्रेस ने कहा, ''क्या केजरीवाल ने हरियाणा में सभी नब्बे सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार कर कांग्रेस को नहीं हरवाया था''

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 फरवरी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बुरी तरह हराने के बाद, भाजपा ने अब अपनी नज़रें पश्चिम बंगाल और बिहार पर केंद्रित कर दी हैं।

तमिलनाडु या केरल जैसे दक्षिणी राज्यों को छोड़ दें तो दिल्ली, बिहार और बंगाल ही अब तक भाजपा के लिए अजेय बने हुए थे। अब जबकि भाजपा ने दिल्ली आम आदमी पार्टी से छीन ली है और अरविंद केजरीवाल को हरा दिया है इसलिए भाजपा नेताओं के दिलों में इन दो पूर्वी राज्यों को जीतने की महत्वाकांक्षाएं फिर से जाग उठी हैं।

दिल्ली में 27 साल के अंतराल के बाद पार्टी के सत्ता में लौटने के बाद आत्मविश्वास से भरे पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्षी नेता सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में यात्रा शुरू करने की योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य 2026 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के शासन को उखाड़ फेंकना है। इसके पहले नवंबर में बिहार में चुनाव होंगे, जहां भाजपा अपने दम पर, नीतीश कुमार के समर्थन के बिना, सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

- कांग्रेस ने क्षेत्रीय पार्टियों, एनसीपी, शिव सेना (यूबीटी), सपा व तृणमूल पर कटाक्ष किया
- कांग्रेस के अनुसार, इन पार्टियों ने सदा यह तर्क दिया है कि कांग्रेस को ''बड़े भाई'' की भूमिका निभानी चाहिये, क्षेत्रीय पार्टियों और छोटी पार्टियों के संदर्भ में तथा उनके हितों को ''अकॉमोडेट'' करना चाहिये तथा आप द्वारा हरियाणा व गोवा में कांग्रेस के खिलाफ पूर्ण तैयारी के साथ चुनाव लड़ने जैसी ''भूल'' को बड़े दिल से स्वीकार कर लेना चाहिये।
- सभी तर्क-वितर्क के बाद, कांग्रेस अब विपक्ष के राष्ट्रीय गठबंधन में अपने ''रोल'' पर पुनर्विचार कर रही है और अगले वर्ष बिहार में आयोजित होने वाले विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे पर, लालू यादव से दो टूक बात करेगी।

दिल्ली चुनावों के रुझान भाजपा को राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभुत्व को पुनः स्थापित करने की उम्मीद देते हैं, जो पिछले साल के लोकसभा चुनावों में बहुमत हासिल करने में असफल रहने के बाद एक तरह से शर्मिंदगी का कारण बन गया था। परिणामों का विश्लेषण करने पर यह सामने आता है कि कांग्रेस उम्मीदवारों की उपस्थिति के कारण आम आदमी पार्टी को लगभग 15

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

परवेश सिंह वर्मा दिल्ली के नये मु.मंत्री होंगे?

अमित शाह के करीबी सूत्रों ने बताया कि 13 फरवरी को प्र.मंत्री मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद परवेश शपथ ग्रहण करेंगे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 फरवरी। भाजपा के दिग्गज नेता परवेश सिंह वर्मा, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराया है, को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, इस प्रकार वे अपने पिता साहिब सिंह वर्मा का सपना पूरा कर सकेंगे, जो एक पुस्तकालयाध्यक्ष थे और 1996 से 1998 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे, उन्हें मदनलाल खुराना की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था।

वह पश्चिम दिल्ली के दो बार पूर्व सांसद और महरौली के विधायक रहे हैं। शनिवार को चुनाव परिणामों के तुरंत बाद, परवेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

शाह से जुड़े सूत्रों ने बताया कि वह 13 फरवरी को पीएम मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

- भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बी.एल. संतोष ने, दिल्ली विधानसभा चुनाव में विजयी भाजपा के 48 विधायकों की बैठक ली।
- 36 वर्षीय परवेश सिंह वर्मा ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्व मु.मंत्री, आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को हराया था।
- परवेश, अपने पिता साहिब सिंह वर्मा के सपने को पूरा करेंगे, मु.मंत्री का पदभार संभाल कर। साबिह सिंह वर्मा एक लाइब्रेरियन थे तथा 1996-1998 तक दिल्ली के मु.मंत्री भी रहे, मदनलाल खुराना के बाद।

रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के पद से इस्तीफा देने के बाद यह कदम उठाया।

राष्ट्रीय संगठन महासचिव बी.एल. संतोष ने भाजपा के 48 नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई, क्योंकि उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने विधानसभा को भंग कर दिया।

'चुनाव प्रक्रिया में सरकारी हस्तक्षेप लोकतंत्र की मौत है'

नयी दिल्ली, 10 फरवरी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि लोकतंत्र में सरकार को चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए और जब भी वह हस्तक्षेप करती है तो लोकतंत्र दम तोड़ने लगता है।

गांधी ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सरकार को चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह का दखल नहीं देना चाहिए। उसे निष्पक्ष रहकर काम करना चाहिए। उनका कहना कि सरकार का चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हमारे देश में यही सब चल रहा है। गांधी ने कहा, चुनावी प्रक्रिया में सरकारी हस्तक्षेप का अर्थ है लोकतंत्र की हत्या - ये खुद संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है और आज हिंदुस्तान में यही हो रहा है।

- राहुल गांधी ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बात खुद बाबा साहेब अम्बेडकर ने कही थी।

नारायण मूर्ति की कंपनी ने ''दमनपूर्वक'' 700 नये कर्मचारियों को नौकरी से निकाला?

पहली बार आई.टी. सैक्टर के कर्मचारियों ने संगठित होकर, इंफोसिस कंपनी के खिलाफ कर्नाटक के श्रम विभाग में ''फॉर्मल'' शिकायत दर्ज की

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 फरवरी। इन्फोसिस एक बार फिर गलत कारणों से सुर्खियों में है। हां, वही कंपनी, जिसे उस व्यक्ति ने स्थापित किया था जो चाहता है कि युवा उसके और उसकी कंपनी के लिए हफ्ते में सत्तर घंटे काम करें, ने सिर्फ कुछ महीने पहले अपने मैसूर कैंपस में भर्ती किए गए 700 युवा आईटी प्रौफैशनल्स को बर्खास्त कर दिया है। जिसके बाद आई.टी. कर्मचारियों के संघ ने कर्नाटक राज्य श्रम विभाग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।

आई.टी. प्रौफैशनल्स यूनियन, नैसैंट इन्फॉर्मेशन टैक्नॉलजी एम्प्लॉईज़ सिनेट (एन.आई.टी.ई.एस.) ने इन्फोसिस द्वारा 700 कर्मचारियों को बर्खास्त करने को अन्यायपूर्ण और अवैध बताया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 700 प्रौफैशनल्स को पिछले साल कैंपस प्लेसमैंट के दौरान भर्ती किया गया था, और कुछ महीनों के भीतर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कुछ मामलों में, युवा महिला प्रौफैशनल्स से, बर्खास्तगी के आदेश के कुछ घंटों के भीतर ही कैंपस छोड़ने को कहा गया।

- यूनियन का कहना है कि अधिकतर बर्खास्त नये कर्मचारियों ने ''एजुकेशन लोन'' ले रखा है, बैंकों से, अब उन ''लोन्स'' का भुगतान कैसे होगा।
- यूनियन के अनुसार, कुछ माह पूर्व, अक्टूबर महीने में इन ''नये कर्मचारियों को देश के विभिन्न कैम्पस से कई इन्टरव्यु लेने के बाद चुना गया था।
- इंफोसिस कंपनी का कहना है, इन नये चयनित कर्मचारियों को, कंपनी के मैसूरु कैम्पस में प्रशिक्षण दिया जा रहा था, पर, लगातार तीन बार मौका देने के बाद भी ये कर्मचारी फण्डामैंटल ट्रेनिंग असैसमैंट पास नहीं कर पाये थे। अतः कंपनी के अनुसार, उनके नियुक्ति पत्र में उल्लिखित ''सैपरेशन एग्रीमैंट'' की शर्तों की अनुपालना में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है।

अधिकांश युवा प्रौफैशनल्स को पिछले अक्टूबर में भर्ती किया गया था, अब इन्हें म्यूचुअल सैपरेशन के पत्र स्वीकार करने और कैंपस छोड़ने के लिए कहा गया, जिससे उन्हें यह सोचने का भी समय नहीं मिला कि उनके साथ क्या हो रहा है। कई इन्फोसिस कर्मचारियों ने, जिन्हें इस तरह से बर्खास्त किया गया, ने अपने इंजीनियरिंग या आईटी पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक ऋण लिया हुआ था।

जिन कर्मचारियों को बाहर जाने के लिए कहा गया, ये वो थे जो इन्फोसिस मैसूर कैंपस में आयोजित बुनियादी प्रशिक्षण आकलन (फाउन्डेशनल ट्रेनिंग असैसमैंट) को पास नहीं कर पाए थे। एक निजी टेलीविज़न चैनल के अनुसार, वो कर्मचारी, जो तीन बार में आकलन पास करने में असफल रहे, को बाहर जाने के लिए कहा गया। कंपनी का दावा है कि उसके अनुबंध टूल में इसका उल्लेख है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राष्ट्रपति मुर्मू ने किया महाकुंभ स्नान

महाकुंभनगर, 10 जनवरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की तीसरी ऐसी प्रथम नागरिक हैं जिन्हें प्रयागराज महाकुंभ में आने और त्रिवेणी में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

मुर्मू ने सोमवार को यहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महाकुंभ के सकुशल संपन्न होने और राष्ट्र कल्याण की कामना के साथ त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगायी। पावन जल धारा के ऊपर बनाई गई जेटी पर तैयार किए गए पूजास्थल पर बैठकर उन्होंने पवित्र त्रिवेणी का पूजन किया। राष्ट्रपति ने मां गंगा की आरती उतारी। महामहिम ने किले में स्थित अक्षयवट, सरस्वती कूप और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन-पूजन किया। उनके साथ राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे।

- मुर्मू भारत की तीसरी राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने कुंभ स्नान किया है। इससे पहले प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद और फिर चौदहवें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी कुंभ स्नान कर चुके हैं।

इससे पहले देश के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद का आगमन 1953 में प्रयागराज के कुंभ में पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर एक माह का कल्पवास भी किया था। सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने किसी तीर्थ पुरोहित के शिविर में न/न रहकर संगम तट पर स्थित अकबर के किले के ऊपर शिविर में अपना कल्पवास पूरा किया था। उस स्थान को अब प्रेसिडेंसियल व्यू के नाम से जाना जाता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'14 करोड़ भारतवासी फूड सिक्यूरिटी एक्ट के तहत मिलने वाले राशन से वंचित'

सोनिया गांधी ने राज्यसभा में शून्यकाल में मामला उठाया कि पिछली जनगणना 2011 में हुई और उसके बाद 2021 में जनगणना हो जानी चाहिये थी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 फरवरी। हर दशक होने वाली जनगणना पर जोर देते हुए कांग्रेस पार्लियामैंट्री पार्टी (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केन्द्र से जनगणना करवाने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि 2011 का डेटा पुराना हो चुका है और इसलिए लगभग 14 करोड़ भारतीय खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं।

नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के पात्र व्यक्तियों को अपडेट करने की अत्यावश्यकता को रेखांकित करते हुए सोनिया ने जनगणना की समय सीमा पर स्थिति स्पष्ट नहीं करने को लेकर सरकार की आलोचना की।

- पर, इस वर्ष के अंत तक भी जनगणना पूरी होने की संभावना नहीं है।
- उन्होंने कहा, ''फूड सिक्यूरिटी एक्ट के तहत लाभान्वितों का चयन पिछले जनगणना के आधार पर ही हो रहा है और इसके कारण ''एलिजबल'' 14 करोड़ भारतीय नागरिक इस एक्ट के तहत मिलने वाली सुविधा, जैसे ''फ्री राशन''' आदि का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं।''

शून्यकाल में राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने जनगणना करवाने में चार साल देरी होने का उल्लेख किया और चिंता जताई कि इस वर्ष भी जनगणना होने की संभावना नहीं है।

उन्होंने कहा, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हर दशक होने वाली जनगणना में 4 साल की देरी हुई है। यह जनगणना 2021 में होनी थी। अभी भी पता नहीं है कि यह कब होगी। बजट आवंटन से पता चलता है कि जनगणना इस वर्ष होने की संभावना भी नहीं है। लगभग 14 करोड़ भारतीय एनएफएसए के तहत अपने हक से वंचित रह जाएंगे।

गांधी ने कहा, ''जरूरत है कि सरकार शीघ्रातिशीघ्र जनगणना करवाने को प्राथमिकता दे और सुश्निचित करे कि सभी पात्र व्यक्तियों को एनएफएसए के तहत आवश्यक लाभ मिले। खाद्य सुरक्षा कोई विशेधाधिकार नहीं है बल्कि मौलिक अधिकार है।'' ज्ञातव्य है कि यह कानून भारत की जनता को खाद्य एवं पोषण की सुरक्षा देने के लिए 2013 में यूपीए सरकार ने लागू किया था। उन्होंने कहा, यह कानून 2013 में यूपीए सरकार ने बनाया था जो 140 करोड़ भारतीयों को खाद्य व भोजन की सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था। इस कानून ने कई परिवारों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, खासकर कोविड-19 के दौरान। यह कानून ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आधार उपलब्ध कराता है।

गांधी ने कहा, एनएफएसए में 75 प्रतिशत आबादी व 50 प्रतिशत शहरी आबादी को अनाज मिलता है। पर, यह कोटा 2011 की आबादी पर आधारित है। इसके तहत पात्र व्यक्ति को प्रतिमाह 5 किलो अनाज मिलता है।''

'30 आप विधायक हमारे सम्पर्क में'

चंडीगढ़, 10 फरवरी। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) की हार और बीजेपी की जीत के बाद पंजाब की राजनीतिक गरमाई हुई है। पंजाब कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि राज्य में बड़ी उथल-पुथल होगी। राज्य में कांग्रेस के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने अब दावा किया है कि आप के 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। बाजवा को दावे के कितना दम है। यह तो आने वाले कुछ दिनों में तय होगा लेकिन पंजाब में भगवंत मान सरकार को खतरे के अटकलों के बीच अरविंद केजरीवाल मंगलवार को विधायकों के साथ बैठक करेंगे। सीएम भगवंत मान और सभी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इसी वजह से पंजाब सरकार की 10 फरवरी को होने वाली कैबिनेट मीटिंग भी टाल दी गई।

- पंजाब के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने यह सनसनीखेज दावा किया।

दिल्ली में आप की हार पर कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कड़ा हमला बोला था। बाजवा ने कहा था कि भगवंत मान अब दूसरे एकनाथ शिंदे बनेंगे। भगवंत मान के आप में अलग गुट बनाने के भी दावे किए गए हैं। बाजवा ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाबियों को बेवकूफ बनाने और 2022 में उनके वोट हासिल करने के लिए पंजाब में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK